

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 392

जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को दिया जाना है

कछार पेपर मिल का बंद होना

392. श्री बदरुद्दीन अज़मल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इससे अवगत है कि हेलाकांडी जिला के पंचग्राम में स्थित हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक इकाई कछार पेपर मिल वित्तीय संकट का सामना कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह पेपर मिल कच्चे माल की कमी के कारण गत कुछ वर्षों से प्रायः बंद होती रही है जिससे भारी घाटा हो रहा है;
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे बंद होने से बचाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) और (ख): जी, हां। कछाड़ पेपर मिल (सीपीएम), हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन (एचपीसी) की एक इकाई, मेघालय राज्य जहां से सीपीएम की 100% आवश्यकता की पूर्ति होती है, में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कोयले के खनन और ढुलाई पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंध के कारण कोयले की अनुपलब्धता से वित्तीय संकट का सामना कर रही है। कोयला अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि सीपीएम परिसर के अंदर कोई ब्रॉड गेज लिंकेज नहीं है।

(ग): जी, हां।

(घ) और (ङ): सीपीएम द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को महसूस करने के बाद भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिसमें यातायात के कारण इसकी प्रचालन लागतों को पूरा करने के लिए सीपीएम की विशेष रूप से संचालन और क्रियान्वयन असुविधाओं को कम करने हेतु अनुदान देना शामिल है। भारी उद्योग विभाग ने कछाड़ पेपर मिल के लिए कार्यशील पूंजी सहायता भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, सरकार ने पंचग्राम स्टेशन से कछाड़ पेपर मिल (सीपीएम) परिसर के अंदर तक मीटर गेज (एमजी) को ब्रॉड गेज (बीजी) में परिवर्तित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई है।

(च): प्रश्न नहीं उठता।
